

37

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1163-तीन/2005 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 11-7-2005 - पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग,
रीवा - प्रकरण क्रमांक 44/2004-05 निगरानी

1- अरुण कुमार 2- अरविन्द कुमार
पुत्रगण वापनन्द ग्राम हटवा चक नं.-1
तहसील हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश

--आवेदकगण

विरुद्ध

रामलाल पुत्र राजनाथ शर्मा
ग्राम हटवा चक नं.-1 तहसील
हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश

----अनावेदक

(आवेदकगण के श्री के.के.द्विवेदी अभिभाषक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक-11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक
44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 के
विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना के यहां आवेदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे क्रमांक 602/4, 603/2, 607/3, 615/3 के नक्शा तरमीम का आवेदन दिया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 8 अ 74/1991-92 पंजीबद्ध हुआ तथा आदेश दिनांक 3-2-1992 पारित करके नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 28 अ-74/91-92 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-9-2001 से निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार वृत्त खटकरी का आदेश दिनांक 3-2-1992 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

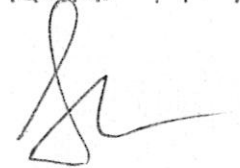
3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनावेदक भूमि खसरा क्रमांक 607 का भूमिस्वामी है तथा सर्वे नंबर 607 के बटा नंबरों के नक्शा तरमीम के समय उसे पक्षकार नहीं बनाया गया एवं नायव तहसीलदार ने भी उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 3-2-92 पारित किया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने अनावेदक द्वारा दिये गये अवधि

विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया है यदि आवेदकगण अपर कलेक्टर के विलम्ब क्षमा करने वावत् दिये गये आदेश से दुखी थे तब उन्हें उंस अंतरिम आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी करना थी, किन्तु इस निगरानी में आवेदक के अभिभाषक द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिया गया तर्क इन्हीं कारणों से माने जाने योग्य नहीं है।

5/ अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 3-9-2001 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी का आदेश दिनांक 3-2-1992 निरस्त करके प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने एवं लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 में अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अपर कलेक्टर एवं आयुक्त रीवा संभाग द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर